www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 340 | जौनपुर, शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ अब भी गंभीर चिंता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति ने कहा है कि बांग्लादेश से भारत में होने वाली अवैध घुसपैठ अब भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। समिति ने सुझाव दिया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त कार्य समूह (जॉइंट वर्किंग ग्रुप) या स्थायी द्विपक्षीय तंत्र बनाया जाए, ताकि संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की राष्ट्रीयता की पुष्टि और उन्हें वापस भेजने (प्रत्यावर्तन) की प्रक्रिया पर नियमित निगरानी रखी जा सके। समिति ने कहा कि वर्तमान में 2,369 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के मामलों में उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि बांग्लादेश सरकार से होना बाकी है। समिति का मानना है कि दोनों देशों के बीच एक समर्पित तंत्र बनने से यह प्रक्रिया तेज होगी और लंबित मामलों का जल्द निपटारा हो सकेगा। समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि जांच के दौरान पूरी सावधानी बरती जाए, ताकि किसी भारतीय नागरिक को गलती से बांग्लादेश न भेज दिया जाए। साथ ही हिरासत में रखे गए सभी लोगों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए और कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल और असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में देखा जा रहा है। हालांकि अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों की है, ।

राम मंदिर चढ़ावा अनियमितता पर विपक्ष का घेराव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राम मंदिर चढ़ावा अनियमितता मामले में विपक्षी नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, ष्हमने कभी किसी का अपमान करने की कोशिश नहीं की, न ही हमारा ऐसा कोई इरादा था और न कभी हो सकता है। हम सभी के दिल में भगवान श्रीराम के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा है। उन्होंने कहा, ष्चढ़ावा अनियमितता मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए।ष राम मंदिर चढ़ावा अनियमितता मामले में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के साधु के वेश में संसद में विरोध प्रदर्शन करने पर समाजवादी पार्टी सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने कहा, ष्पप्पू यादव ट्रस्ट के सदस्य के कपड़े पहनकर वहां आए थे। जिस तरह से ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर चढ़ावे की चोरी की है, उसके मुख्य आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया।ष राम मंदिर चढ़ावा अनियमितता मामले में राजद सांसद मीसा भारती ने कहा, ष्सिर्फ सदस्य ही इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठा रहे हैं बल्कि पूरे देश के लोग भी सरकार से पूछना चाहते हैं ।

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 से बढ़ेगी प्रदेश की वैश्विक पहचान, व्यापार और विनिर्माण को मिलेगा बढ़ावा

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार, विनिर्माण और निर्यात के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) का चौथा संस्करण आगामी 25 से 29 सितम्बर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार, उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो ने पिछले तीन संस्करणों में प्रदेश के उत्पादों, उद्यमों और उद्योगों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बनाया है। अब यह आयोजन केवल एक व्यापार प्रदर्शनी नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्मेक इन इंडियाश और श्मेक फॉर द वर्ल्डश के विजन को आगे बढ़ाने वाला वैश्विक मंच बन चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश यानी श्अनलिमिटेड पोटेंशियलश का प्रदेश है और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इस सामर्थ्य को अनुभव करने का सबसे प्रभावी मंच है। उन्होंने निर्देश दिए कि देश और विदेश में इस आयोजन का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए,

ताकि अधिक से अधिक निवेशक, खरीदार और आगंतुक इसमें सहभागी बनें। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष ट्रेड शो की थीम श्यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथरू इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्सश रखी गई है। आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.50 लाख से अधिक पंजीकृत बी2बी खरीदारों, 4.50 लाख से अधिक बी2सी आगंतुकों तथा 85 देशों से 550 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 4000 से अधिक एमओयू, 3200 करोड़ से अधिक प्रस्तावित एमओयू मूल्य और 13 हजार 500 करोड़ से अधिक बिजनेस इंक्वायरी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित अन्य देशों के साथ भी सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि इस बार ओडीओपी, ओडीओसी, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, रक्षा एवं एयरोस्पेस, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, पर्यटन एवं फिल्म, अक्षय ऊर्जा, ऑटो एवं इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मा एवं स्वास्थ्य, कौशल विकास किया।

लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पारित, केशव प्रसाद मौर्य ने बताया ऐतिहासिक कदम

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्यसभा में 'लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026' के पारित होने का ऐतिहासिक कदम बताया है। उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्यसभा में 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' का पारित होना देश के करोड़ों मेहनती एवं प्रतिभाशाली युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उप मुख्यमंत्री के अनुसार यह विधेयक परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय बनाने की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह महत्वपूर्ण कदम परीक्षा माफियाओं और अनुचित साधनों पर प्रभावी अंकुश लगाकर योग्य अभ्यर्थियों के परिश्रम को उनका उचित सम्मान दिलाने का कार्य करेगा। एक मजबूत, ईमानदार और जवाबदेह परीक्षा व्यवस्था ही विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव है, और यह विधेयक उसी संकल्प को नई शक्ति प्रदान करता है।

नया परीक्षा बिल छात्रों का भविष्य करेगा सुरक्षित, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा – अमित शाह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 के पास होने को छात्रों के भविष्य के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। एक्जिक्यूटिव ब्रांच गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, मोदी सरकार ने आज संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 पास करके हमारे छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है।ष उन्होंने कहा कि यह नया कानून उन अपराधों को रोकने के लिए सबसे मजबूत उपाय साबित होगा जो हमारी सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को कम करके हमारे युवाओं की उम्मीदों को नुकसान पहुंचाते हैं। शाह ने कहा कि मेरिट–आधारित व्यवस्था की निष्पक्षता से छेड़छाड़ करने की कोशिश करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने के प्रावधानों के जरिए यह कानून यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे युवा अपने देखे हुए सपनों को पूरा कर सकें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बिल के पारित होने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, ष्आज राज्यसभा में श्सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने से पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली को नई मजबूती मिली है।ष शिवराज सिंह चौहान ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम बताया। उन्होंने कहा, श्प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, यह परीक्षा प्रणाली को भ्रष्टाचार और पेपर लीक के डर से मुक्त करने और इसे विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

मरोसेमंद रेगुलेटरी सिस्टम जरूरी, भारत दुनिया की फार्मेसी बनकर करेगा वैश्विक सहयोग - जेपी नड्डा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फर्स्ट ग्लोबल ड्रग रेगुलेटरी कॉन्क्लेव 2026 के उद्घाटन सत्र में भारत के रेगुलेटरी विजन को दुनिया के सामने रखा। इस दो दिवसीय कॉन्क्लेव में दवा और मेडिकल उपकरणों की सुरक्षा, गुणवत्ता और नवाचार को लेकर वैश्विक सहयोग पर जोर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भरोसेमंद, विज्ञान–आधारित और पारदर्शी रेगुलेटरी सिस्टम सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही, यह इनोवेशन को बढ़ावा देता है और मरीजों तक सुरक्षित, असरदार, उच्च–गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं पहुंचाने में मदद करता है। नड्डा ने रेगुलेटरी सुधारों, डिजिटल बदलाव और मजबूत क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के जरिए भविष्य के लिए तैयार रेगुलेटरी इकोसिस्टम बनाने करने, रेगुलेटरी तालमेल, क्षमता निर्माण और वैज्ञानिक साझेदारियों के जरिए वैश्विक सहयोग को और गहरा करना जरूरी है। उन्होंने इस

बात पर भी जोर दिया कि उभरती वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने और दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए सभी देशों को मिलकर सामूहिक प्रयास करने के भारत के संकल्प को दोहराया। भारत को दुनिया की फार्मेसी बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक दवा आपूर्ति में बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में जानकारी साझा होंगे। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य विभिन्न देशों के रेगुलेटर्स को एक मंच पर लाकर दवा सुरक्षा के नए मानक तय करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्या सलिला श्रीवास्तव ने भी कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र तेजी से आपस में जुड़ रहा है और तकनीक हर दिन बदल रही है। ऐसे में रेगुलेटरी सिस्टम को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा। इसके लिए बेहतर अंतरराष्ट्रीय सहयोग, पारदर्शिता, वैज्ञानिक उत्कृष्टता और आपसी भरोसा जरूरी है। आधुनिक रेगुलेटर्स की जिम्मेदारी सिर्फ नियम बनाना नहीं है। उन्हें इनोवेशन को बढ़ावा देने के साथ–साथ एक मजबूत, भरोसेमंद और विज्ञान पर आधारित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के जरिए।

नागरिकों की शिकायतों को सुनने के लिए एमएचएडीए में एक अलग सेल का गठन किया जाए - देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएचएडीए) के निर्माण और पुनर्विकास के संबंध में नागरिकों के विचारों को सुनने के लिए एक अलग सेल के गठन का निर्देश दिया है। मुंबई महानगर क्षेत्र सहित राज्य में विभिन्न विकास और आवास परियोजनाएं चल रही हैं, और उन्होंने इनमें विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित एक बैठक में राज्य में एमएचएडीए की विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर आवास राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर, विधायक सचिन कल्याणशेट्टी, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, बृहन्मुंबई नगर निगम

आयुक्त अश्विनी भिडे, शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, एमएचएडीए के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायसवाल और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एमएचएडीए द्वारा चलाई जा रही आवास परियोजनाओं के कारण आने वाले वर्षों में आम आदमी के लिए बड़ी संख्या में घर उपलब्ध होंगे। इन सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना चाहिए। बीडीडी चाली जैसी पुनर्वास परियोजनाएं, जहां निवासियों को स्थानांतरित किया जाना है, तुरंत पूरी की जानी चाहिए और परियोजना पर काम में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कमाठीपुरा में महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए, पुलों, सड़कों आदि की व्यवहार्यता पर विचार किया जाना चाहिए और संपर्क सड़कों के विस्तार पर भी विचार किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति संजीव जायसवाल ने बताया कि एमएमआर क्षेत्र में एमएचएडीए कुल 37 लाख करोड़ रुपए की 15 विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है और इस सामूहिक पुनर्विकास परियोजना के तहत 21 लाख से अधिक फ्लैट बनाए जाएंगे।

तेजस्वी यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में राजद के जीत की भविष्यवाणी की

पटना, (एजेंसी)। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान खत्म होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने जीत का दावा करना शुरू कर दिया है। राजनीति बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया कि 3 अगस्त को वोटों की गिनती के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) जीतेगी। राजद ऑफिस पहुंचने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे कई लोगों को चौंका देंगे। उन्होंने दावा किया कि राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता को हर जाति, धर्म और सामाजिक समूह के वोटरों का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा, ष्बांकीपुर के लोग इस बार लालटेन को वोट दे रहे हैं। बांकीपुर में लालटेन चमकेगी। हमें हर वार्ड और हर पोलिंग बूथ से वोट मिले हैं।ष राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि पूरे चुनाव क्षेत्र से पार्टी को जो फीडबैक मिला है, उससे पता चलता है कि राजद हर वार्ड में आगे है। उनके अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने के लिए वोटर पार्टी के साथ एकजुट हो गए हैं। भारत राष्ट्रीय समाचार उन्होंने आरोप लगाया कि तीन दशकों से ज्यादा समय तक बांकीपुर सीट पर कब्जा होने के बावजूद, भाजपा इस क्षेत्र में पर्याप्त विकास सुनिश्चित करने में नाकाम रही है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी से जनता की नाराजगी राजद और उसकी उम्मीदवार के लिए समर्थन में बदल गई है। उन्होंने कहा, ष्इस बार बांकीपुर में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा।

बच्चों को चरित्रवान बनाने की हो हर संभव कोशिश - डीआईओएस

(डॉ अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या।एसएसवी इंटर कॉलेज में गुरुवार को आयोजित शिक्षक अभिभावक संघ के शैक्षिक सत्र 2026–27 के प्रथम आमसभा बैठक को संबोधित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ.पवन कुमार तिवारी ने कहा कि बच्चों के लालन – पालन में अभिभावक जिस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, उसी तरह की चुनौतियों का सामना प्रधानाचार्य, शिक्षक और शिक्षा विभाग के सामने भी होती है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. तिवारी ने कहा कि वेबसीरीज को देखकर समाज और बच्चों में जो बदलाव आ रहा है, वही बदलाव बच्चे अपने खुद के जीवन में लागू कर रहे हैं। जाहिर है कि ऐसा करते हुए वह संस्कार से विमुख हो रहे हैं। टीवी स्क्रीन एक राक्षस है, जो धीरे – धीरे जीवन शैली बदल रहा है। यह समाज के सामने बड़ी चुनौती है। डीआईओएस डॉ.तिवारी ने कहा कि आज के परिवेश में भले ही बच्चे ज्ञानवान कम बनें लेकिन उन्हें चरित्रवान बनाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। बच्चों को परिवार की जरूरत है, टीवी या सीरियल की नहीं। इस बात को जितना जल्दी समझना लिया जाए, उतना अच्छा है। अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो आज का मनोरंजन है, वही कल का चरित्र, अनुभव, ज्ञान और शिक्षा बनेगा। ऐसे में सोशल मीडिया से खुद भी दूर रहें और बच्चों को भी दूर रखें। बच्चे की परवरिश और चरित्र स्कूल के ही भरोसे नहीं छोड़े। इस पर स्कूल और परिवार दोनों को ध्यान देना होगा।प्रधानाचार्य डॉ. मणि शंकर तिवारी ने कहा कि शिक्षक आंतरिक और अभिभावक वाह्य स्तर पर छात्रों के सर्वांगीण विकास में मददगार होते हैं। दोनों के समन्वय से ही शिक्षण कार्य में सफलता मिलती है। शिक्षक अभिभावक संघ के उपाध्यक्ष के तौर पर प्रधानाचार्य डॉ. तिवारी ने बैठक के एजेंडा बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने आय – व्यय को भी सदन के समक्ष रखा। जिसका सभी ने करतल ध्वनि से अनुमोदन किया। विद्यालय के श्याम सुंदर इको क्लब की ओर से संचालित की जा रही गतिविधियों की अभिभावकों ने मुक्त कंठ से सराहना की। बच्चों की ओर से कराए गए पौधारोपण को भी सराहा गया। अध्यक्षीय उद्बोधन संघ के अध्यक्ष अशुतोष मिश्रा ने व्यक्त किया।शिक्षक अभिभावक संघ के मंत्री शिक्षक अरुण कुमार दुबे ने पिछली कार्यवाही सभी के समक्ष रखी। जिसका सदन ने सर्व सम्मति से सहर्ष अनुमोदन किया। शैक्षिक उन्नयन की योजना पर भी विचार विमर्श किया गया। अन्य वक्ताओं ने भी कहा की किसी भी विद्यालय की प्रगति उसके शैक्षिक उन्नयन और शैक्षिक गतिविधियों पर निर्भर करती है। जो संघर्ष करते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। सभी ने शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिए कई सुझाव दिए और विद्यालय की गतिविधियों समेत पठन–पाठन की सराहना की।जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ.पवन कुमार तिवारी ने विद्यालय में नवनिर्मित अत्याधुनिक जिम का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ऐसे में स्वास्थ्य कारणों के लिए विद्यालय का यह कदम सराहनीय है। जिम में ट्रेडमिल, बटरफ्लाई, स्क्वैड मशीन, साइकिल, डेडलिफ्ट, बेटलिफ्ट, बेंचप्रेस सहित कई उपयोगी उपकरण हैं। जो शिक्षक और विद्यार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी साबित होंगे।बैठक को शिक्षक अभिभावक संघ के विशेष आमंत्रित सदस्य पूर्व अध्यक्ष रमाकांत पांडेय, पूर्व अध्यक्ष जयसराज वर्मा, राम नेग गौतम और डॉ. धनश्याम यादव, वरिष्ठ शिक्षक सुरेंद्र देव तिवारी, डॉ.देवेंद्र कुमार मिश्रा, वारिज नयन शर्मा, अवधेश सिंह, नंद किशोर उपाध्याय सहित अभिभावक राजेंद्र कुमार दुबे, अमित तिवारी, अजय पाण्डेय, अजीत श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। इस दौरान शिक्षक राजीव शुक्ला, जय प्रकाश चौरसिया, जग प्रसाद मौर्या, रामचंद्र, स्नेहा सिंह,अनुपम कुमार, जयेंद्र पाठक सहित विद्यालय के सभी शिक्षक और 300 से अधिक अभिभावक मौजूद रहे।

संपादकीय

रोजगार निजी अनुबंध पर टिका

कोई नाविक किसी खास रूट (जैसे होरमुज) से गुजरने से मना करता है, तो कंपनी उसका अनुबंध रद्द कर सकती है या श्ल्लैकलिस्ट्च कर सकती है। इससे उसका भविष्य दांव पर लग सकता है। भारत सरकार ने पश्चिम एशिया में भारतीय नाविकों के हमलों का शिकार बनने के बाद भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए श्सीफेयरर–फर्स्ट आपातकालीन सुरक्षा योजनाच्य लागू की है। शिपिंग कंपनियों और भर्ती एजेंसियों को अगले निर्देश तक होरमुज मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों को तैनात ना करने के निर्देश दिए गए हैं। मगर क्या इससे भारतीय नाविक सचमुच सुरक्षित हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए अहम है, क्योंकि कागजी सरकारी आदेश और समुद्र की कड़वी हकीकत में कोई मेल नजर नहीं आता। इसलिए अंदेशा गहरा है कि इस सरकारी पहल को लागू करना मुश्किल साबित होगा। नाविक शिपिंग कंपनियों (या उनकी नौकरी भर्ती एजेंसियों) के कर्मचारी होते हैं, भारत सरकार के नहीं। उनका रोजगार निजी अनुबंध पर टिका होता है। नाविक किसी विदेशी या भारतीय शिपिंग कंपनी या किसी थर्ड–पार्टी मैनिंग एजेंसी के साथ छह से नौ महीने का कांट्रैक्ट साइन करते हैं। इसके तहत कोई नाविक किसी खास रूट (जैसे होरमुज) से गुजरने से मना करता है, तो कंपनी उसका अनुबंध रद्द कर सकती है या श्ल्लैकलिस्ट्च कर सकती है। इससे उसका भविष्य दांव पर लग सकता है। नौवहन बाजार में भी काम पाने भारी होड़ है। यही कारण है कि नाविक अक्सर जोखिम लेकर भी कहीं जाने को तैयार हो जाते हैं। दुनिया में तमाम नाविकों के बीच भारतीयों की संख्या लगभग 17 प्रतिशत है। जबकि अधिकांश जहाज पनामा, लाइबेरिया, या मार्शल आइलैंड्स जैसे देशों के झंडे तले रजिस्टर्ड हैं, भले उनके मालिक किसी देश के हों। ऐसे में भारतीय नाविकों पर उस देश का कानून लागू होता है, जिसके नाम पर जहाज पंजीकृत है। भारत सीधे किसी विदेशी जहाज के रूट को लेकर दखल नहीं दे सकता। तो फिर सरकार इस फैसले को लागू कैसे करवाएगी? अधिक से अधिक वह रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट एजेंसियों एजेंसियों पर दबाव डाल सकती है कि वे नाविकों को जबरन खतरे वाले क्षेत्रों में ना भेजें। नाविकों को श्राइट टू रिफ्यूजच्य के तहत युद्ध क्षेत्र में जाने से इनकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। लेकिन वे ऐसा करियर को दांव पर लगाते हुए ही कर पाएंगे। यही इस मामले का पेच है।

छात्रों और युवाओं को भरोसा बना

एस. सुनील

प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा और परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार की जो पहल की है उस पर छात्रों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के बाहर सार्वजनिक रूप से भी दिखने लगी है। उन्होंने जो नियम बनाने और विधायी कदम उठाने की पहल की है और युवाओं से सीधी अपील की है उसका असर यह हुआ है कि आंदोलन की नैतिक ताकत बने सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी और इसके साथ ही आंदोलन की तीव्रता काफी कम हो गई। इसकी व्यापकता भी धीरे धीरे कम हो रही है। पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन की जिन तस्वीरों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि देश का युवा खास कर श्जेन जीच्य केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गया है वह देश की प्रतिनिधि तस्वीर नहीं है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उन तस्वीरों से देश की वास्तविकता नहीं जाहिर हो रही है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पेपर लीक की घटना, जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्वंय कहा, श्जघन्य पाप्च है। लेकिन आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इसमें शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले इसके लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पर भी किसी को संदेह नहीं है। देश का युवा वर्ग और छात्रों का भी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा सीधा जुड़ाव या संवाद है कि वे इस मामले में प्रधानमंत्री की गंभीरता को समझ रहे हैं। तभी गुरुवार, 23 जुलाई की रात को प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सीधे युवाओं को श्फ्रेंड्स्च्य कह कर संबोधित किया। अपने मोबाइल से वीडियो बना कर उन्होंने पोस्ट किया और अगले दिन यानी शुक्रवार की रात को बताया कि उस पर कितनी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। गुरुवार रात के प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम वीडियो ने रिकॉर्ड बनाया। करीब 35 करोड़ लोगों ने उसे देखा और पेपर लीक से लेकर परीक्षा में सुधार के अनेक सकारात्मक सुझाव दिए, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने अगले वीडियो में किया। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा और परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार की जो पहल की है उस पर छात्रों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के बाहर सार्वजनिक रूप से भी दिखने लगी है। उन्होंने जो नियम बनाने और विधायी कदम उठाने की पहल की है और युवाओं से सीधी अपील की है उसका असर यह हुआ है कि आंदोलन की नैतिक ताकत बने सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी और इसके साथ ही आंदोलन की तीव्रता काफी कम हो गई। इसकी व्यापकता भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसका कारण यह है कि देश के युवाओं को अपने प्रधानमंत्री और उनके संकल्पों पर भरोसा है। उनको विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। इसके रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी उनको दूर किया जाएगा। बहरहाल, पेपर लीक को लेकर भी प्रधानमंत्री की पहल पर एक साथ कई काम शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को कैबिनेट की विशेष बैठक संसद भवन के अंदर हुई, जिसमें द पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रीवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब सरकार पेपर लीक और परीक्षा में अक्सर होने वाली दूसरी गड़बड़ियों को रोकने के लिए ज्यादा सख्त कानून बनाने जा रही है। इसे मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते के शुरू में ही पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी चर्चा करा कर कानून बनाया जाए। इसमें पेपर लीक के दोषियों के लिए 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक की घटना की जांच दो महीने में होगी और तीन महीने के अंदर अदालत में ट्रायल पूरा करके फैसला सुनाया जाएगा। इस संशोधन बिल को मंजूरी देने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक से जुड़ी घटनाओं की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आदेश दे दिया था। इस बिल में इस पूरी प्रक्रिया को वैधानिक स्वरूप देने का प्रावधान भी किया गया है। इस मामले में सरकार की गंभीरता इस बात से दिखाई देती है कि मेडिकल में दाखिले के लिए नीट यूजी परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के 47 कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया गया है। सरकार एनटीए का भी पुनर्गठन करने वाली है ताकि परीक्षा की प्रक्रिया को किसी भी तरह की लीक और गड़बड़ी से सुरक्षित किया जा सके। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वंय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं इसलिए युवाओं को और उनके अभिभावकों को भी भरोसा बना है। उनको लग रहा है कि सरकार परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। ध्यान रहे पहले ही इस बात की घोषणा हो चुकी है कि अगले साल नीट यूजी की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। इससे भी छात्रों और युवाओं को भरोसा बना है। दूसरी ओर अगर विपक्षी पार्टियों का रवैया देखें तो वह बहुत निराशाजनक दिखेगा। उनकी तरफ से किसी तरह का रचनात्मक सुझाव सरकार के सामने नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है। उनकी ओर से सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। जिस समय जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ उस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विदेश में थे।

पंजाब चुनाव से पहले नया नैरेटिव गढ़ने का प्रयास, वारिस पंजाब दे के प्रदर्शन ने खड़े किए बड़े सवाल

नीरज

हम आपको बता दें कि चंडीगढ़ में अकाली दल वारिस पंजाब दे के बैनर तले हुए प्रदर्शन के दौरान उस समय नाटकीय दृश्य देखने को मिला, जब पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाटर कैनन वाहन पर एक प्रदर्शनकारी चढ़ गया। पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की राजनीति में एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश तेज होती दिखाई दे रही है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है कि कट्टरपंथी राजनीति को जनभावना का पर्याय बना दिया जाए। इसी कड़ी में एक दिन पहले चंडीगढ़ में हुए प्रदर्शन ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतांत्रिक विरोध के नाम पर कानून व्यवस्था को चुनौती देना और युवाओं को उग्र राजनीति की ओर धकेलना पंजाब के भविष्य के लिए शुभ संकेत है? देखा जाये तो राज्य के लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चुनावी जमीन तैयार करने के लिए भावनात्मक मुद्दों को हथियार बनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि चंडीगढ़ में अकाली दल वारिस पंजाब दे के बैनर तले हुए प्रदर्शन के दौरान उस समय नाटकीय दृश्य देखने को मिला, जब पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाटर कैनन वाहन पर एक प्रदर्शनकारी चढ़ गया। हालात तब और तनावपूर्ण हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ को तितर–बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन पूरे घटनाक्रम ने यह संकेत दिया कि विरोध प्रदर्शन अब केवल मांगों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन और टकराव की राजनीति का माध्यम बनते जा रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में तो यह भी दावा किया गया कि प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय के लिए पुलिस के वाटर कैनन वाहन पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। हम आपको बता दें कि यह प्रदर्शन वारिस पंजाब दे के सांसद अमृतपाल सिंह और अन्य सिख नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारी पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन चंडीगढ़–मोहाली सीमा पर भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग के कारण उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई और माहौल लंबे समय तक तनावपूर्ण बना रहा। हालांकि इस पूरे आंदोलन को केवल एक रिहाई अभियान के रूप में देखना बड़ी भूल होगी। इसके पीछे कहीं अधिक व्यापक राजनीतिक रणनीति दिखाई देती है। अमृतपाल सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद चुने गए थे और अब वारिस पंजाब दे ने उन्हें 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। ऐसे में लगातार हो रहे प्रदर्शन उनके राजनीतिक प्रभाव को जीवित रखने और उन्हें राज्य की राजनीति के केंद्र में बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखे जा रहे हैं। वारिस पंजाब दे का दावा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अमृतपाल सिंह की निरोधात्मक हिरासत समाप्त हो चुकी है, इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर सरकार और अदालतों का कहना है कि 2023 के अजनाला पुलिस स्टेशन हमले समेत कई गंभीर आपराधिक मामलों के कारण उनकी हिरासत जारी है और उन्हें अस्थायी राहत देना राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। यही वजह है कि उनकी रिहाई संबंधी याचिकाओं को लगातार खारिज किया गया है। इस आंदोलन का

एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग को तथाकथित ष्बंदी सिंहष् के मुद्दे से जोड़कर व्यापक धार्मिक और भावनात्मक समर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे आंदोलन को केवल एक व्यक्ति तक सीमित रखने की बजाय उसे व्यापक पंथिक विमर्श का रूप देने की रणनीति अपनाई गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे संगठन पारंपरिक सिख राजनीति पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। यही वह बिंदु है जहां वारिस पंजाब दे की विचारधारा और उसकी कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। लोकतंत्र में किसी भी नागरिक या संगठन को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, लेकिन यदि आंदोलन का स्वरूप लगातार टकराव, उग्र नारों, कानून व्यवस्था को चुनौती देने और युवाओं में व्यवस्था–विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने वाला बन जाए, तो यह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं रह जाता। ऐसी राजनीति समाज में ध्रुवीकरण बढ़ा सकती है और पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य को फिर से वैचारिक अस्थिरता की ओर धकेलने का खतरा पैदा कर सकती है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह आंदोलन कई संदेश देता है। एक ओर यह आम आदमी पार्टी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है ताकि किसी भी सख्त कार्रवाई को ष्सिख विरोधी करार दिया जा सके, वहीं दूसरी ओर यह शिरोमणि अकाली दल के पारंपरिक पंथिक वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति भी माना जा रहा है। लगातार सड़क पर उतरकर संगठन अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहता है कि वह स्वयं को पंजाब की नई राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करने की तैयारी में है। बहरहाल, पंजाब के मतदाताओं के सामने आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे भावनात्मक नारों और उग्र राजनीति की बजाय राज्य के विकास, रोजगार, शिक्षा, नशे की समस्या और कानून व्यवस्था जैसे वास्तविक मुद्दों को प्राथमिकता दें। लोकतंत्र में असहमति आवश्यक है, लेकिन यदि चुनावी लाभ के लिए कट्टरपंथी सोच और टकराव की राजनीति को सामान्य बनाने की कोशिश की जाती है, तो उसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ सकता है। इसलिए पंजाब के लोगों को हर राजनीतिक नैरेटिव का गंभीरता से मूल्यांकन करना होगा और ऐसे किसी भी प्रयास से सतर्क रहना होगा जो समाज को बांटने या युवाओं को उग्र विचारधारा की ओर मोड़ने का माध्यम बन सकता है।

बांग्लादेश से व्यापार के लिए पुतिन ने भारतीय रुपए पर लगाया दाँव

नीरज

रूस ने बांग्लादेश के साथ भारतीय रुपये में व्यापार करने का प्रस्ताव देकर दक्षिण एशिया की भू–राजनीति में नई हलचल पैदा की तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अपने राजदूत सर्जियो गोर को तुरंत ढाका जाने का निर्देश दे डाला। इन दोनों घटनाक्रमों को साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ नजर आती है। एक ओर रूस अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए भारत की वित्तीय ताकत का सहारा लेकर बांग्लादेश को अपने साथ जोड़ना चाहता है, वहीं दूसरी ओर चीन और रूस के साथ ढाका की बढ़ती नजदीकियों ने वॉशिंगटन की चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि इसी वजह से ट्रंप प्रशासन ने अपने शीर्ष राजनयिक को ढाका भेजने का फैसला किया है। भारत के लिए यह घटनाक्रम इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें रुपया, क्षेत्रीय कूटनीति और हिंद–प्रशांत की बदलती रणनीतिक राजनीति एक साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि रूस ने बांग्लादेश को प्रस्ताव दिया है कि दोनों देशों के बीच होने

वाला व्यापार भारतीय रुपये में निपटाया जाए। इसके साथ ही मॉस्को एक विशेष भुगतान तंत्र विकसित करने, ढाका में रूसी बैंक की शाखा खोलने तथा प्रत्यक्ष बैंकिंग संपर्क स्थापित करने की भी पहल कर रहा है। यह प्रस्ताव रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंधों से उत्पन्न वित्तीय संकट का सीधा जवाब है। प्रतिबंधों के कारण रूसी बैंक वैश्विक भुगतान प्रणाली से काफी हद तक कट गए हैं और इसी वजह से मॉस्को चीन, तुर्किये और भारत जैसे देशों के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की नीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि रूस ने चीनी युआन की बजाय भारतीय रुपये को प्राथमिकता दी है। इससे पहले रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के ऋण भुगतान के लिए युआन का विकल्प सामने आया था, लेकिन चीन और बांग्लादेश के बैंक अमेरिकी प्रतिबंधों के जोखिम के कारण भुगतान प्रक्रिया का हिस्सा बनने से हिचक गए। परिणामस्वरूप अरबों डॉलर की ऋण किस्तें अभी भी सोनाली बैंक में रूस के नाम खोले गए खाते में फंसी हुई हैं। ऐसे में भारतीय रुपया रूस के लिए अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक और विश्वसनीय विकल्प बनकर उभरा है। यह भारत की वित्तीय विश्वसनीयता और रुपये के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय महत्व का भी संकेत है। बताया जा रहा है कि सितंबर या अक्टूबर में होने वाली बांग्लादेश–रूस अंतर–सरकारी आयोग की बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा होगी। हम आपको बता दें कि रूस केवल भुगतान व्यवस्था तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि रूस–बांग्लादेश बिजनेस काउंसिल, वस्त्र निर्यातकों का पंजीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश, लघु एवं मध्यम उद्योगों के सहयोग तथा कृषि और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने का भी प्रस्ताव लेकर आया है। मॉस्को ने बांग्लादेश को अंतरराष्ट्रीय बाजार से 10 डॉलर प्रति टन कम कीमत पर लगभग 2.8 लाख टन यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराने की पेशकश भी की है। इसके अलावा सूरजमुखी तेल, दालों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्यात में भी रुचि दिखाई है। दूसरी ओर ढाका प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार, कृषि, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को अपनी प्राथमिकता बना रहा है। देखा जाये तो सामरिक दृष्टि से यह घटनाक्रम भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि रूस और बांग्लादेश के बीच व्यापार भारतीय रुपये में होता है, तो यह दक्षिण एशिया में रुपये के अंतरराष्ट्रीय उपयोग को नई गति देगा। इससे डॉलर आधारित भुगतान प्रणाली पर निर्भरता कम होगी और भारत एक क्षेत्रीय वित्तीय सेतु के रूप में उभर सकता है। यह भारत की उस दीर्घकालिक रणनीति के भी अनुकूल है जिसके तहत वह रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण और वैकल्पिक वित्तीय तंत्र के निर्माण पर जोर दे रहा है। इसी पृष्ठभूमि में सर्जियो गोर का 30 जुलाई का ढाका दौरा विशेष महत्व प्राप्त करता है। सर्जियो गोर, जो दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत होने के साथ भारत में अमेरिका के राजदूत भी हैं, वह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मुलाकात कर रहे हैं। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब प्रधानमंत्री तारिक रहमान हाल ही में चीन की यात्रा कर चुके हैं और बीजिंग के साथ व्यापार, आर्थिक गलियारे तथा रक्षा सहयोग को नई गति देने पर सहमति बनी है। विशेष रूप से बांग्लादेश–म्यांमार आर्थिक गलियारे के चीनी प्रस्ताव ने वॉशिंगटन की चिंता बढ़ा दी है। यही वह बिंदु है जहां पूरी तस्वीर स्पष्ट होती है। रूस आर्थिक मोर्चे पर बांग्लादेश को अपने साथ जोड़ना चाहता है, चीन अवसंरचना और सामरिक संपर्क के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जबकि अमेरिका इस बढ़ती रूस–चीन धुरी को संतुलित करने के लिए सक्रिय हो गया है। सर्जियो गोर का ढाका दौरा इसी रणनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन यह समझता है कि यदि बांग्लादेश रूस और चीन के साथ गहरे आर्थिक एवं सामरिक रिश्ते विकसित करता है, तो बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद–प्रशांत तक शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसलिए वॉशिंगटन अब ढाका की विदेश नीति की प्राथमिकताओं को प्रत्यक्ष रूप से समझना और उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखना चाहता है। दूसरी ओर, भारत के लिए यह पूरा घटनाक्रम अवसर इसलिए है कि रूस भारतीय रुपये को क्षेत्रीय भुगतान की धुरी बनाना चाहता है और बांग्लादेश पहले से ही भारत के साथ कुछ व्यापार रुपये में करता है। साथ ही भारत के लिए यह घटनाक्रम चुनौती भी है क्योंकि यदि चीन का आर्थिक गलियारा और रूस की वित्तीय व्यवस्था समानांतर रूप से मजबूत होती है, तो दक्षिण एशिया की भू–राजनीति पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगी। भारत को ऐसे समय संतुलित कूटनीति, मजबूत आर्थिक संपर्क और क्षेत्रीय नेतृत्व के माध्यम से अपनी भूमिका को और सुदृढ़ करना होगा। बहरहाल, स्पष्ट है कि यह केवल व्यापारिक प्रस्ताव या एक राजनयिक यात्रा की कहानी नहीं है। यह उस नए एशियाई शक्ति–संतुलन का संकेत है जिसमें डॉलर की जगह स्थानीय मुद्राएं, प्रतिबंधों की जगह वैकल्पिक वित्तीय तंत्र और पारंपरिक गठबंधनों की जगह बहुध्रुवीय समीकरण तेजी से आकार ले रहे हैं। बांग्लादेश इस नई भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनता दिख रहा है और भारत उसकी धुरी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

जंतर–मंतर पर मोदी की युवाओं के लिए कहानी लड़खड़ा गई

रवींद्रन

प्रदर्शनकारी असल में सरकार को बता रहे थे कि यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है। एक उम्मीदवार जो सालों तक पढ़ता है और फिर देखता है कि उसकी परीक्षा रद्द हो गयी है, वह भारत के युवाओं के फायदे को एक मौके के तौर पर नहीं देखता। एक परिवार जो अपनी बचत कोचिंग पर खर्च करता है और फिर पेपर में गड़बड़ी के आरोपों का सामना करता है। केंन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आखिरकार नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। मौजूदा हालात में मंत्री और मोदी सरकार के लिए इससे अच्छा सम्मानजनक रास्ता नहीं हो सकता था।धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को निजी दुश्मनी से चलाया जा रहा अभियान बताने का कोई ठोस आधार नहीं है। न तो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और न ही जंतर–मंतर पर जमा हुए युवा प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के खिलाफ किसी निजी शिकायत को अपनी लामबंदी के केन्द्र में रखा है। उनका मामला राजनीतिक और संस्थागत थारू प्रधान एक ऐसे मंत्रालय के मुखिया थे जिसकी देखरेख में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की साख बुरी तरह से गिर गई है, और वे चाहते हैं कि सर्वोच्च स्तर पर जिम्मेदारी तय हो।यह फर्क मायने रखता है। सरकारें अक्सर असहज आंदोलनों का जवाब उनका नेतृत्व करने वालों के मकसद, जुड़ाव या शख्सियत पर सवाल उठाकर देती हैं। ऐसे तरीके कुछ समय के लिए ध्यान भटका सकते हैं, लेकिन वे इस मुख्य आरोप का जवाब नहीं दे सकते कि जिंदगी तय करने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को बार–बार पेपर लीक, परीक्षाओं को रद्द करने, गड़बड़ियों और प्रशासनिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ा है। प्रदर्शनकारी सिर्फ दलालों, अधिकारियों या आपराधिक बिचौलियों को सजा देने की मांग नहीं कर रहे थे। वे एक ऐसे शासन की संस्कृति को चुनौती दे रहे थे जिसमें शिम्मेदारी नीचे जाती दिखती है जबकि बड़े अधिकारी सुरक्षित रहते हैं।इस आंदोलन ने प्रधान को एक अकेले मंत्री से कहीं ज्यादा बना दिया। वह एक ऐसी परीक्षा मशीनरी का सार्वजनिक चेहरा बन गए हैं जिसे लाखों युवा भारतीय अब भरोसेमंद नहीं मानते। उनके इस्तीफे की मांग इसलिए नहीं की जा रही थी कि हर लीक का सीधा संबंध उनके ऑफिस से हो, बल्कि इसलिए की जा रही थी कि मंत्री की शिम्मेदारी का मतलब तभी होता है जब राजनीतिक आधिकारिकता के नतीजे प्रणाली की नाकामी के हों। सरकार के जवाब ने चुपचाप संकट की गंभीरता को मान लिया है। अधिकारियों को हटा दिया गया है, परीक्षा की जगह पर भर्ती के तरीकों पर फिर से विचार किया जा रहा है, पेपर लीक के खिलाफ कड़े कदम उठाने का वादा किया गया है और फास्ट–ट्रैक न्यायिक प्रणाली की पेशकश की गई है। विरोध करने वाले प्रतिनिधियों के साथ बातचीत जारी है, जबकि केंद्र ने प्रधान से जुड़ी मांग पर और समय मांगा। ये किसी मामूली प्रदर्शन का सामना कर रहे प्रशासन की कार्रवाइयां नहीं थीं। ये सरकार की तरफ से एक ऐसे मुद्दे को नियंत्रित करने की कोशिश के संकेत थे जो परीक्षा प्रबंधन से आगे बढ़कर राजनीतिक वैधता के दायरे में आ गया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल में भी वह दबाव दिखा। छात्रों से उनकी अपील और जवाबदेही का भरोसा तब आया जब आंदोलन बढ़ गया था, जंतर–मंतर पर टकराव तेज हो गया था और पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें बड़े पैमाने पर फैल गई थीं। देरी ने उनके संदेश का असर कम कर दिया। जब तक प्रधानमंत्री ने बात की, तब तक झगड़ा सिर्फ एक लीक हुए पेपर का नहीं रह गया था। यह प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं, घटते नौकरी के मौकों, प्रशासनिक नाकामियों की वजह से सालों की तैयारी के खराब होने और इस सोच पर गुस्से का जमाव बन गया था कि आम उम्मीदवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है जबकि ताकतवर संस्थाएं जांच से बच जाती हैं। यहीं पर आंदोलन सीधे सरकार की बड़ी राजनीतिक शब्दावली से टकराया। मोदी ने लगातार भारत की युवा आबादी को डेमोग्राफिक डिविडेंड और विकसित भारत के पीछे मुख्य ताकत के तौर पर पेश किया है। फिर भी डेमोग्राफिक डिविडेंड नारों, आबादी के आकार या प्रेरक भाषणों से नहीं बनता है। यह भरोसेमंद शिक्षा, सही भर्ती, रोजगार बढ़ाने और इस भरोसे पर निर्भर करता है कि पैसे, हेरफेर या लीक हुए प्रश्नपत्र तक पहुंच से काबिलियत को हराया नहीं जाएगा। प्रदर्शनकारी असल में सरकार को बता रहे थे कि यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है। एक उम्मीदवार जो सालों तक पढ़ता है और फिर देखता है कि उसकी परीक्षा रद्द हो गयी है, वह भारत के युवाओं के फायदे को एक मौके के तौर पर नहीं देखता। एक परिवार जो अपनी बचत कोचिंग पर खर्च करता है और फिर पेपर में गड़बड़ी के आरोपों का सामना करता है, वह संस्थागत सुधार को एक भाववाचक प्रशासनिक सवाल के तौर पर नहीं देखता। उनके लिए, नाकामी

तुरंत वित्तीय रूप से नुकसानदेह और अक्सर बहुत बुरा होता है। आंदोलन के भौतिक फैलाव पर नजर खास तौर पर जरूरी है। यह किसी बड़ी विपक्षी पार्टी की संगठनात्मक मशीनरी से शुरू नहीं हुआ था। इसकी भाषा, इसके प्रतीक और एकत्रीकरण ज्यादातर युवाओं से ही निकले, जबकि विपक्षी नेता आंदोलन की अपनी रफ्तार पकड़ने के बाद ही इसमें शामिल हुए। इससे सरकार के लिए विरोध प्रदर्शनों को एक आम राजनीतिक पार्टी वाला अभ्यास कहकर खारिज करना मुश्किल हो गया। यहां तक कि जहां राजनीतिक पार्टियां गुस्से को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं, वहां भी उन्होंने ऐसे हालात नहीं बनाए जिनसे यह गुस्सा पैदा हुआ। पुलिस पाबंदियां, हिरासत, निगरानी और संचार माध्यमों में रुकावटें विरोध की जगह को नियंत्रित कर सकती हैं, लेकिन वे भरोसा वापस नहीं ला सकतीं। परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में, जरूरत से ज्यादा सख्ती बरतने से प्रशासनिक जवाबदेही की मांग, लोकतांत्रिक जवाबदेही पर एक बड़ी बहस में बदल सकती है। निराश उम्मीदवारों को कानून–व्यवस्था की समस्या के तौर पर देखने की हर कोशिश प्रदर्शनकारियों की इस बात को और मजबूत करती है कि सरकार अपनी बदनामी छिपाने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है, न कि अपनी नाकामियों को सुधारने में। इसलिए, प्रधान के इस्तीफे की मांग का एक प्रतीकात्मक महत्व बन गया है। उन्हें हटाने से अकेले परीक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो जाएगी।

त्रिलोचन महादेव धाम पहुंचे डीएम–एसपी, व्यवस्थाओं का लिया जायजाय कमियों पर जताई नाराजगी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में सावन माह और कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. एवं पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने शुक्रवार को पौराणिक त्रिलोचन महादेव धाम का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंदिर परिसर में साफ–सफाई और प्रकाश व्यवस्था में कमियां मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मंदिर परिसर, बैरिकेडिंग, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि सावन और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने मंदिर परिसर की नियमित साफ–सफाई, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम की तैनाती तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी राम विलास को फटकार लगाते हुए कहा कि चिन्हित कमियों को तत्काल दूर किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को पूरी सतर्कता और अनुशासन के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन, यातायात संचालन और कानून–व्यवस्था बनाए रखने में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी। निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने भगवान त्रिलोचन महादेव का विधिवत दर्शन–पूजन कर जनपद की सुख–समृद्धि एवं शांति की कामना की। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक गोल्डी गुप्ता, उपजिलाधिकारी आतिश कुमार, क्षेत्राधिकारी केराकत अजय राय, थाना प्रभारी जलालपुर सतेंद्र विक्रम सिंह, खंड विकास अधिकारी राम विलास, मंदिर संरक्षक सोनू गिरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

पारिवारिक विवाद तंग थाने में तैनात सिपाही ने विषाक्त पदार्थ का किया सेवन, गंभीर हालत में वाराणसी रेफर

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर के बरसठी थाने में तैनात एक सिपाही ने शुक्रवार को कथित रूप से पारिवारिक विवाद के बाद विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। साथी पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया गया। लेकिंग परिजन जनपद के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज करवा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, मिर्जापुर निवासी सिपाही विवेक गौड़ पिछले दो वर्षों से बरसठी थाने में मुंशी के पद पर तैनात हैं। शुक्रवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे उन्होंने अपने परिजनों से वीडियो कॉल पर बातचीत की। इसके कुछ देर बाद उन्होंने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। साथ में मौजूद एक अन्य सिपाही ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और अधिकांश पदार्थ गिरा दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि विवेक गौड़ ने बचा हुआ कुछ हिस्सा पी लिया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना परिसर में अफरा–तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. अशोक यादव ने बताया कि सिपाही को प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है।हालत ठीक नहीं है। घटना से पहले सिपाही ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर एक भावनात्मक संदेश साझा किया था, जिसमें लिखा था कि ष्इस जीवन में कोई नहीं अपना, सब मतलब के हैं।ष् पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल सिपाही का जौनपुर के निजी नर्सिंग होम में उपचार चल रहा है।वही इस मामले में जानकारी लेने पर क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूं विजय चौधरी ने बताया कि पत्नी से विवाद के कारण सिपाही ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया है हालात स्थिर है निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है।मामले की छानबीन की जा रही है।परिजनों द्वारा कोई तहरीर नहीं मिली है।

कांग्रेस ने 10 हजार पौधों का किया नि : शुल्क वितरण, 10 लाख पौधे लगाने का लिया संकल्प

जौनपुर, 31 जुलाई (हि.स.)। यूपी के जौनपुर में पर्यावरण संरक्षण और हरित अभियान को गति देने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को शहर में पौध वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान के नेतृत्व में बड़ी मस्जिद के निकट आयोजित कार्यक्रम में 10 हजार पौधों का निरूशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि जौनपुर कांग्रेस पूरे जनपद में अपने स्तर से 10 लाख पौधे लगाने का अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक कदम है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़–पौधे प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने, शुद्ध प्राणवायु उपलब्ध कराने, वर्षा चक्र को संतुलित रखने और बढ़ती गर्मी के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई पर चिंता व्यक्त करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए जनभागीदारी पर जोर दिया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि वृक्ष प्रकृति और मानव जीवन के आधार हैं। यदि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो पौधे लगाने के साथ–साथ उनकी देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने सभी नागरिकों से अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण के अभियान से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों को निरूशुल्क पौधे वितरित किए तथा पौधों के संरक्षण की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पं. बंशीधर शर्मा, सभासद शहनवाज मंजूर, सभासद अबुजर शेख, राजकुमार गुप्ता, जैद सिद्दीकी, अजीम जौनपुरी, साद सिद्दीकी, मसूद अहमद, सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हाईटेंशन तार से झुलसे बालक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर लगाया जाम, घायल को एंबुलेंस में लेकर किया प्रदर्शन

दीपक श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में केराकत तहसील क्षेत्र में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसे 10 वर्षीय बालक के परिजनों ने शुक्रवार को मुआवजे की मांग को लेकर मनिहार मोड़ पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान घायल बालक को भी एंबुलेंस में घटनास्थल पर लाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। केराकत थाना क्षेत्र के पूरनपुर गांव निवासी राकेश कुमार के 10 वर्षीय पुत्र किशन कुमार 14 जुलाई को दोपहर करीब 12 बजे हाईटेंशन तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया था। घटना के बाद उसे स्थानीय अस्पताल से जिला अस्पताल और फिर बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया। परिजनों का आरोप है कि घटना के 15 दिन बीत जाने के बावजूद उन्हें कोई आर्थिक सहायता या मुआवजा नहीं मिला। बच्चे के इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ होने के कारण ग्रामीणों के सहयोग से उसका उपचार कराया जा रहा है। किशन के पिता राजगीर मिस्त्री का कार्य करते हैं। शुक्रवार अपराह्न करीब तीन बजे परिजनों और ग्रामीणों ने मनिहार मोड़ पर सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन की ओर से मुआवजा देने का आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान घायल बालक एंबुलेंस में ही मौजूद रहा। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर जाम समाप्त कराने का प्रयास किया। हालांकि, परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे और मौके पर उपजिलाधिकारी को बुलाने की मांग करते रहे। प्रदर्शनकारियों ने आपातकालीन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अन्य एंबुलेंसों के आवागमन में बाधा नहीं आने दी। फिलहाल पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी परिजनों से वार्ता कर स्थिति सामान्य कराने के प्रयास में जुटे हैं।

हत्या के प्रयास के पांच आरोपित गिरफ्तार, वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, लाठी व ईंट बरामद

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। शाहगंज थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे पांच आरोपितों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक कुल्हाड़ी, एक लाठी तथा एक ईंट बरामद की है। गिरफ्तार आरोपितों को न्यायालय भेज दिया गया।इस मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी शाहगंज गिरेन्द्र सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं तथा प्रभारी निरीक्षक तेज बहादुर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, शाहगंज थाना क्षेत्र के समैसा गांव में 30 जुलाई को प्रवेश पुत्र छद्दू अपने परिजनों के साथ ट्यूबवेल के पास धान की रोपाई के लिए गया था। आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसी रामस्वारथ और उसके परिजनों ने गाली–गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर धारदार हथियार एवं लाठी से हमला कर दिया, जिससे प्रवेश, महिमा और पुष्पा गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में वादी छद्दू की तहरीर पर शाहगंज थाने में विभिन्न धाराओं में सात नामजद आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपितोंकृधीरज गौतम, रामस्वारथ, विद्या देवी, सीमा तथा पूतला उर्फ रिंका, सभी निवासी ग्राम समैसा, थाना शाहगंजकृ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, लाठी और ईंट भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने सभी आरोपितों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। शेष नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देगा निःशुल्क कानूनी सहायता

लखनऊ, (संवाददाता)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लागू 'चाइल्ड–फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रेन स्कीम–2024' के तहत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क, सुलभ, सुरक्षित और बाल–अनुकूल विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद और संवेदनशील परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को समयबद्ध न्याय, कानूनी संरक्षण और पुनर्वास सुनिश्चित करना है।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के प्रभारी सचिव जीवक कुमार सिंह ने बताया कि यह योजना उन सभी बच्चों के लिए लागू है, जो किसी भी प्रकार की कानूनी या सामाजिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इसके अंतर्गत विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, बाल श्रम, मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, लैंगिक हिंसा, बाल विवाह, दिव्यांग, अनाथ, परित्यक्त, गुमशुदा तथा अन्य कमजोर और संवेदनशील परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रशिक्षित पैनल अधिवक्ताओं, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, पैरा–लीगल वॉलंटियर्स तथा अन्य प्रशिक्षित विधिक कर्मियों की सहायता से बच्चों को न्यायालयीन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में कानूनी सहयोग दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों को आवश्यक परामर्श, पुनर्वास, मुआवजा दिलाने, सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि उन्हें समग्र सहायता मिल सके।प्रभारी सचिव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समितियों, फ्रंट ऑफिस, पुलिस थानों, बाल न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, बाल देखरेख संस्थाओं, जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेंटर तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक पात्र बच्चे तक समयबद्ध और प्रभावी विधिक सहायता पहुंचे।

25 हजार रुपये का इनामी बदमाश गिरफ्तार, भैंस व पिकअप चोरी के मामलों में था वांछित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, 31 जुलाई। यूपी के जौनपुर में मीरगंज थाना अंतर्गत पुलिस ने शुक्रवार को अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान के तहत 25 हजार रुपये के इनामी वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है आरोपित भैंस चोरी और पिकअप चोरी के दो मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) आतिश कुमार सिंह के दिशा–निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी मछलीशहर के नेतृत्व में मीरगंज पुलिस ने वांछित अभियुक्त सुजीत सरोज पुत्र शोभनाथ, निवासी करौरा, थाना मछलीशहर को गिरफ्तार किया। इस संबंध में जानकारी लेने पर क्षेत्राधिकारी मीरगंज प्रतिमा वर्मा ने बताया कि तीन अक्टूबर 2025 को मीरगंज थाना क्षेत्र के चौकी खुर्द निवासी केशव गौतम ने अपनी भैंस चोरी होने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं 23 सितंबर 2025 को करियांव निवासी जैन कुमार बिंद ने घर के सामने खड़ी अपनी पिकअप चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों मामलों की विवेचना के दौरान सुजीत सरोज का नाम प्रकाश में आया, जिसके बाद वह फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध चोरी, आर्म्स एक्ट तथा आबकारी अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में जौनपुर के मछलीशहर, मीरगंज और गौराबादशाहपुर थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।पुलिस द्वारा जिले में वांछित एवं इनामी अपराधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

जिलाधिकारी-एसपी ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण, बंदियों से संवाद कर परखी व्यवस्थाएं

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. एवं पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने शुक्रवार को जिला कारागार का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा एवं बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं नियमानुसार समाधान के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा सुविधा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने बंदियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया और कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी बंदियों को निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अधिकारियों ने जेल चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने भर्ती बंदियों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ चिकित्सकों से उपचार व्यवस्था, उपलब्ध दवाओं तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बीमार बंदियों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जाए तथा गंभीर रोगियों की विशेष निगरानी रखी जाए। निरीक्षण के दौरान कारागार परिसर की साफ–सफाई, रसोईघर, भोजन वितरण व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रबंधों का भी जायजा लिया गया। अधिकारियों ने जेल प्रशासन को सभी व्यवस्थाएं सुचारु बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी नगर गोल्डी गुप्ता, जेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

हज–2027 के लिए सऊदी अरब में प्रतिनियुक्ति का अवसर

लखनऊ, (संवाददाता)। हज–2027 के सफल संचालन के लिए भारतीय कौंस्लावास, जद्दाह (सऊदी अरब) में अस्थायी प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इसके तहत मुस्लिम पुरुष एवं महिला सरकारी कर्मचारियों से को–ऑर्डिनेटर (प्रशासन), हज अधिकारी तथा हज सुपरिटेंडेंट के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 10 अगस्त, 2026 तक निर्धारित पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार को–ऑर्डिनेटर (प्रशासन) के पद के लिए अखिल भारतीय सेवा अथवा संगठित केंद्रीय सिविल सेवा के ग्रुप 'ए' श्रेणी के ऐसे अधिकारी पात्र होंगे, जिनका वेतन ग्रेड लेवल–12 या 13 हो। हज अधिकारी के पद के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकार की सशस्त्र पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल अथवा राज्य पुलिस के ग्रेड लेवल–8 से 11 तक के अधिकारी आवेदन कर सकते हैं।इसी प्रकार हज सुपरिटेंडेंट के पद के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकार के सशस्त्र पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल, राज्य पुलिस तथा ग्रुप 'बी' और 'सी' के स्थायी कर्मचारी पात्र होंगे। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, लोक प्रशासन, संकट प्रबंधन तथा इंजीनियरिंग से जुड़े विशेषज्ञों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन पदों के लिए वेतन ग्रेड लेवल–4 से 7 निर्धारित किया गया है।सभी आवेदकों के लिए 28 जुलाई, 2026 तक आयु 25 से 45 वर्ष के बीच होना तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों की सऊदी अरब में अस्थायी प्रतिनियुक्ति अप्रैल 2027 से जुलाई 2027 तक प्रस्तावित है।

जौहर विश्वविद्यालय पर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

लखनऊ, (संवाददाता)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं पूर्व मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पहुंचकर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त किए जाने की प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठे छात्रों और शिक्षकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की कार्रवाई को शिक्षा विरोधी, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की।प्रदेश प्रभारी ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरनारत छात्रों एवं शिक्षकों का समर्थन करते हुए कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विश्वविद्यालय को बचाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी और छात्रों–शिक्षकों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।उन्होंने कहा कि फिलहाल मुरादाबाद मंडल के आयुक्त द्वारा विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, लेकिन सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उनका कहना था कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को राजनीतिक दुर्भावना का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए।रामपुर प्रवास के दौरान राजेन्द्र पाल गौतम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। इसके बाद उन्होंने पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां की पत्नी एवं पूर्व सांसद तंजीम फातिमा से मुलाकात कर विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।प्रदेश प्रभारी ने कहा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राष्ट्रवादी, पत्रकार और शिक्षाविद् मौलाना मोहम्मद अली जौहर की स्मृति में की गई थी।

दो साल पहले पास हुई जल निकासी योजना, अब तक नहीं हो सकी पूरी

लखनऊ, (संवाददाता)। दो साल पहले कुर्सी रोड पर जलभराव की समस्या दूर करने के लिए शासन ने योजना मंजूर की थी। बजट भी स्वीकृत किया था, मगर काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। स्थिति यह है कि काम पूरा न होने से अब बजट भी अटक गया है। ऐसे में लोगों की समस्या कागज पर ही रह गई। यह काम पूरा हो गया होता तो इलाके की दो लाख से अधिक आबादी को जलभराव से राहत मिलती। कुर्सी रोड रोड मिश्रपुर, गुडंबा व आसपास के इलाके में हर बरसात में जलभराव होता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए स्थानीय निवासी वीरेंद्र सिंह ने नगर निगम से लेकर शासन तक प्रयास किया। इसके बाद शासन ने राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत जल निकासी की कार्ययोजना मंजूर की, जिसमें मिश्रपुर से कुकरैल तक करीब दो किमी भूमिगत नाला (आरसीसी ह्यूम पाइप) निर्माण की मंजूरी दी। इसके लिए करीब तीन करोड़ का बजट मंजूर किया गया। परियोजना मंजूर होने के बाद करीब 950 मीटर ही भूमिगत नाला बना और उसके बाद से काम ठप है। वहीं, जल निकासी प्रोजेक्ट के लिए बजट जारी करने से पहले नगर विकास अनुभाग दो के अनुसचिव संजय कुमार तिवारी की ओर से यह सवाल उठाया गया कि जब टेंडर 2.13 करोड़ रुपये का है तो फिर तीन करोड़ रुपये का बजट जारी करने की मांग क्यों की गई थी। कार्ययोजना में पाइप डालने के अलावा मैनहोल निर्माण और अन्य कौन से कार्य शामिल हैं।

चार माह से फरार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा, अन्य आरोपियों की तलाश जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के बिजनौर थाना क्षेत्र में उधार के रुपये के लेन–देन को लेकर हुए विवाद के बाद युवक की आत्महत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब चार माह से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त तरुण गाबा और संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के निर्देश पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) मो. मुस्ताक के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) रल्लापल्ली वंसथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर अभिषेक कुमार पाण्डेय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बिजनौर कपिल गौतम के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया।पुलिस के अनुसार, 11 मार्च 2026 को सीमा यादव ने बिजनौर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके पति विजय कुमार यादव ने कुछ लोगों को रुपये उधार दिए थे। जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आरोप है कि इसी उत्पीड़न से परेशान होकर विजय कुमार यादव ने आत्महत्या कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय सूचना तंत्र और मैनुअल जांच के आधार पर आरोपी सुमित रावत को गिरफ्तार किया। आरोपी सुबेदार खेड़ा का निवासी है और वर्तमान में बदालीखेड़ा, थाना सरोजनीनगर क्षेत्र में रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

पठन संस्कृति का निर्माण थीम पर जनपद के नोडल संकुल हेतु दो दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

अयोध्या।जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू), अयोध्या द्वारा रूम टू रीड इंडिया के सहयोग से "पठन संस्कृति का निर्माण थीम पर जनपद के नोडल संकुल हेतु दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), अयोध्या में किया गया। कार्यशाला 29 एवं 30 जुलाई 2026 को दो अलग–अलग बैचों में संपन्न हुई।प्रथम बैच का प्रशिक्षण 29 जुलाई को तथा द्वितीय बैच का प्रशिक्षण 30 जुलाई को कराया गया। दोनों बैचों को मिलाकर कुल 131 नोडल शिक्षकों ने प्रशिक्षण में सहभागिता की।कार्यशाला की शुरुआत बालगीत एवं परिचय सत्र से हुई। रूम टू रीड इंडिया टीम द्वारा संस्था के उद्देश्यों एवं एफएलएन डीपीएमयू अयोध्या के कार्यों की जानकारी दी गई।प्रशिक्षण के प्रमुख सत्रों में पुस्तकालय प्रबंधन (लाइब्रेरी मैनेजमेंट) एवं रीडिंग कॉर्नर संचालन,मौखिक भाषा विकास हेतु प्रभावी प्रश्न–निर्माण की तकनीकें, शब्दन्यात्णक जागरूकता, वर्ण ज्ञान एवं शब्द–भंडार विकास,शिक्षक निर्देशिका (टीचर्स गाइड) अनुसार ब्लेंडिंग एवं वर्ड ग्रिड के माध्यम से शब्द वाचन धाराप्रवाह वाचन एवं पठन बोध (रीडिंग फ्लुएंसी एवं कॉम्प्रिहेंशन) हेतु रणनीतियाँ,साप्ताहिक आकलन प्रक्रिया एवं उपचारात्मक शिक्षण (रेमेडियल टीचिंग) रणनीतियाँ दोनों बैचों के प्रशिक्षण के अंत में दिन भर की प्रमुख सीख का समेकन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य नोडल संकुल को बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता (एफएलएनधनिपुण भारत मिशन) के अंतर्गत बच्चों की पठन क्षमता सुदृढ़ करने हेतु सशक्त बनाना रहा।इस मौके पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लाल चन्द जी ने कहा कि पठन संस्कृति को विकसित करने के लिए रूम टू रीड संस्था द्वारा विद्यालयों को विभिन्न रुचिकर पुस्तकें एवं अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराकर प्रशंसनीय प्रयास किया जा रहा है।उन्होंने सभी नोडल संकुलों को निर्देशित किया कि अपने–अपने संकुल के सभी विद्यालयों की समय–सारणी में सभी कक्षाओं के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार पुस्तकालय हेतु एक कालांश निर्धारित किया जाए, जिसमें शिक्षक और बच्चे साथ में पुस्तक पढ़ें और समृद्धि चर्चा करें।प्रशिक्षण में संदर्भदाता के रूप में अयोध्या जनपद के एसआरजी अंबिकेश त्रिपाठी एवं अमित मिश्रा तथा रूम टू रीड संस्था से धीरेंद्र मिश्रा, सौरभ सिंह परिहार एवं मोनिका सिंह उपस्थित रहे। प्रशिक्षण रूम टू रीड इंडिया टीम द्वारा संचालित किया गया।

जन्मदिन पर माँ के नाम रक्तदान, रेड क्रॉस का जनजागरुकता अभियान

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहाँपुर' इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य अग्रज जौहरी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर शासकीय मेडिकल कॉलेज, शाहजहाँपुर के रक्तकोष विभाग में स्वैच्छिक रक्तदान कर युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उन्होंने ष्माँ ने दिया जीवनदान, हम दें रक्तदानष् जनजागरूकता अभियान का शुभारंभ करते हुए सभी युवाओं से अपने जन्मदिवस पर रक्तदान करने का आह्वान किया। रक्तदान के उपरांत अग्रज जौहरी ने रक्तदान प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए उसे रक्तकोष विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ जीतू राज सिंह को वापस सौंपते हुए कहा कि यदि उनका यह रक्त किसी जरूरतमंद की जान बचाने में सहायक बन सके, तो यही उनके जीवन का सबसे बड़ा उपहार होगा। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, जनपद शाखा के सचिव डॉ विजय जौहरी ने बताया कि जन्मदिन केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने का भी श्रेष्ठ अवसर है। उन्होंने कहा कि जब कोई शिशु जन्म लेता है, तब उसकी माता गर्भावस्था और प्रसव के दौरान अनेक कष्ट सहकर उसे जीवन प्रदान करती है। प्रसव के समय रक्तस्राव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी त्याग, ममता और समर्पण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जन्मदिवस पर रक्तदान का संकल्प एक प्रेरणादायक सामाजिक संदेश बन सकता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार माँ अपने त्याग, ममता और संघर्ष से नई पीढ़ी को जीवन देती है, उसी प्रकार प्रत्येक स्वस्थ युवा यदि अपने जन्मदिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान का संकल्प ले, तो वह मातृऋण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ–साथ किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का भी श्रेष्ठ माध्यम बन सकता है। डॉ विजय जौहरी ने कहा कि एक यूनिट रक्त कई मरीजों के उपचार में सहायक होता है तथा दुर्घटना, शल्य चिकित्सा, प्रसूति, थैलेसीमिया एवं अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए जीवनरक्षक सिद्ध होता है। यदि प्रत्येक स्वस्थ युवा अपने जन्मदिवस पर रक्तदान करने का संकल्प ले, तो रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है। उन्होंने सभी युवाओं से रेडक्रॉस के ष्जन्मदिवस पर रक्तदान जीवनदानष् जनजागरूकता अभियान से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि रक्तदान केवल रक्त का दान नहीं, बल्कि किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में नई आशा का संचार करने का सबसे महान माध्यम है। इस अवसर पर रक्तकोष विभाग के चिकित्सकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अग्रज जौहरी को जन्मदिवस की शुभकामनाएँ दीं तथा उनके इस प्रेरणादायी सामाजिक कार्य की सराहना की।

मिशन शक्ति फेज–2 (पांचवा चरण) के अंतर्गत छात्राओं को किया जागरूक

रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव' 'पाली–(हरदोई)' शुक्रवार को पाली कस्बे के सेठ बाबूराम भारतीय इण्टर कालेज में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पाली थाना प्रभारी

निरीक्षक विजय कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार महिला आरक्षी संगीता चौहान के नेतृत्व में संचालित हुआ।

बीकापुर विद्युत उपकेंद्र की कुर्सी हुई आबाद

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।विद्युत उपकेंद्र बीकापुर में काफी समय से तैनात रहे अवर अभियंता शैलेश यादव के स्थानांतरण के बाद पिछले कई दिनों से खाली चल रही कुर्सी आबाद हो गई है। विद्युत विभाग में नए अवर अभियंता (जेई) महेश कुमार पांडेय ने बीकापुर पहुंच कर अपना कार्यभार ग्रहण किया किया गया है। उन्होंने उपखंड कार्यालय बीकापुर के अंतर्गत 33ध्11 केवी विद्युत उपकेंद्र बीकापुर ग्रामीण पहुंचकर चार्ज संभाला। इसके साथ ही उन्हें अतिरिक्त रूप से मंगारी–खजुरहट विद्युत उपकेंद्र का भी कार्यभार सौंपा गया है।

महिला एसओ आशा शुक्ला ने मिशन शक्तिअभियान के तहत महिला पुलिस कर्मियों के साथ छात्राओं व महिलाओ को किया जागरुक

अयोध्या।शुक्रवार को एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर तथा मिशन शक्ति फेज 5 के नोडल प्रभारी व एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी के निर्देश पर सीओ सिटी श्रीयेश त्रिपाठी की देखरेख मे महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने मिशन शक्ति के तहत शहर के विभिन्न कॉलेज और चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने कॉलेज तथा चौक सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर छात्राओं व महिलाओ को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक किया।इस मौके पर उन्होंने मिशन शक्ति अभियान फेज फाइव के तहत सुरक्षात्मक उपाय भी बताई।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी देते हुए बताया कि जिससे कभी भी संकट के समय आप अपनी सुरक्षा कर सकती हैं।इस मौके पर उन्होंने महिलाओ व बालिकाओं से कहीं।उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए जहां एक तरफ उनके विकास को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण सुकन्या समृद्धि योजना सहित एक से बढ़कर एक कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं चल रही हैं।इस मौके पर उन्होंने वहां पर मौजूद बालिकाओं को पंपलेट व बैनर पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना का अंदेशा हो तो बिना झिझक अपने नजदीकी पुलिस कर्मियों, महिला थाना तथा अपने परिजनों को फोन पर बताये।इस मौके पर उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।

हमारे वैचारिक पुरखे हैं प्रेमचंद – स्वप्निल श्रीवास्तव'

(राजा तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। प्रगतिशील लेखक संघ और जनवादी लेखक संघ, फैजाबाद के संयुक्त तत्वावधान में 'प्रेमचंद जयंती' के अवसर पर 'साहित्य, समाज और राजनीति पर प्रेमचंद की वैचारिक विरासत' विषय पर गोष्ठी का आयोजन होटल आभा होटल पर हुआ।इस अवसर पर अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ कवि–साहित्यकार स्वप्निल श्रीवास्तव ने कहा कि प्रेमचन्द हमारे लिए एक वैचारिक पुरखे की तरह हैं। उन्होंने सोच और विचार के स्तर पर जो प्रस्थान बिंदु हमें दिए वे आज भी एक पथ प्रदर्शक की तरह हैं। अपना वक्तव्य देते हुए आलोचक रघुवंशमणि ने कहा कि प्रेमचन्द ने साहित्य के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदल दिया। उनकी विश्वदृष्टि का आज महत्व बढ़ गया है।1980 के बाद भारतीय समाज और साहित्य में प्रेमचन्द की वापसी हुई जिसका कारण सत्ता में प्रतिगामी और सर्वसत्ता वादी ताकतों का आना रहा है। प्रेमचन्द की प्रगतिशील दृष्टि हमारे लिए प्रकाशस्तंभ के समान है जो हमें भविष्य में दूर तक और देर तक रास्ता दिखाती रहेगी। कवि–चिंतक आर डी आनंद ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य हृदय परिवर्तन से शुरू होकर यथार्थ वाद की अभिव्यक्ति तक जाता है। उनके यथार्थवाद की वास्तविक चेतना गतिशीलता में है जो गोदान में धनिया के प्रतिरोध के रूप में फूटता है। लेखिका विनीता कुशवाहा ने कहा कि प्रेमचंद को पढ़ते हुए हम एक यथार्थ की यात्रा पर चले जाते हैं। समाज के दबे कुचले वर्ग के दारुण यथार्थ का सटीक चित्रांकन प्रेमचंद की रचनाओं में मिलता है। कवि–प्राध्यापक विशाल श्रीवास्तव ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि प्रेमचंद की वैचारिक विरासत इसीलिए समृद्ध है क्यूँकि वह अपने समय की हर विषमता को अत्यंत सजग दृष्टि से देखने के कघयल थे। उनकी परख करने के लिए गहरी राजनैतिक समझ के साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लैस होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत के हर कोने सहित समूचे विश्व में प्रेमचंद की स्वीकार्यता उनकी परंपरा और जीवनमूल्य की परिचायक है। जनमोर्चा की संपादक डॉ सुमन गुप्ता ने कहा कि हिंदी का सामान्य पाठक भी प्रेमचंद से अवश्य परिचित होता है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जिस शोषण को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है, यह विसंगति है कि वह आज भी मौजूद है। आज भी समाज में अस्पृश्यता के उदाहरण दिखाई देते हैं। ऐसे में प्रेमचंद का बार–बार याद आना स्वाभाविक है। वरिष्ठ शायर रामजीत यादव बेदार ने कहा कि ईदगाह कहानी के माध्यम से प्रेमचंद तत्कालीन समाज में स्त्रीश्रम के प्रति संवेदना का एक पाठ प्रस्तुत करते हैं। समाज के यथार्थ को सहज रूप में समझाने का काम एक ही लेखक कर सकता था, वह थे मुंशी प्रेमचंद। मो जफर ने कहा कि प्रेमचंद ने अपने उर्दू लेखन में भी समाजी मसाइल को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि आज प्रेमचंद के बारे में बात करने के लिए इतने लोग इकट्ठा हैं, यह बहुत मानीखेज है। डॉ राजकिशोर ने कहा कि प्रेमचंद की कहानियों में वर्णित पीड़ा का तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा कवयित्री पूजा श्रीवास्तव ने कहा कि एक युवा के रूप में मुझे प्रेमचन्द आश्वस्त करते हैं कि आज की नई पीढ़ी को किस प्रकार के लेखकीय आदर्श की आवश्यकता है। युवा पत्रकार नाजिश फातिमा ने कहा कि आज के समय में प्रेमचंद से अधिक प्रासंगिक कोई दूसरा लेखक नहीं है। वे हर युग में समकालीन नजर आते हैं। प्रेमचंद का लेखन अत्यंत व्यापक है और वे समाज के हर पहलू को स्पर्श करते हैं। युवा लेखक विंध्यमणि ने कहा कि आज प्रेमचंद जैसे किसी लेखक का होना असंभव है, उनके जैसी व्यापक दृष्टि का लेखक अब कहीं दीखता नहीं। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन देते हुए सत्यभान सिंह जनवादी ने कहा कि प्रेमचंद समूचे विश्व में सदैव प्रासंगिक रहेंगे। कार्यक्रम में अशोक कुमार तिवारी, राजीव श्रीवास्तव, अखिलेश सिंह, मुजम्मिल फिदा, रामदास सरल, अयोध्या प्रसाद तिवारी, प्रेरणा, डॉ रणजीत वर्मा, विनय करुण, मांडवी सिंह, चन्द्रभान, उमाकांत विश्वकर्मा, जय प्रकाश श्रीवास्तव, प्रशांत आनंद, शिवांगी नंद, कुमकुम भाग्य,शैलेन्द्र सिंह,महावीर पाल सहित बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी, संस्कृति कर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद रहे।

असहाय गरीब तथा निम्न वर्ग की सैकड़ो महिलाओं ने थामा सपा का दमन

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।विधानसभा बीकापुर की पिपरी जलालपुर निषाद बस्ती की महिलाए तथा गोसाईगंज विधानसभा की रतनपुर तेंदुआ की महिलाओं ने च्च। के नेता सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव में आस्था जताते हुए समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित

समरजीत के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने समाजवादी झंडा थमने का काम किया।पंडित समरजीत ने कहां– भाजपा सरकार में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों तथा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर से ऊब चुकी गरीब तथा असहाय महिलाएं गांव–गांव समाजवादी पार्टी का दामन थाम रही है और जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है उससे यह साफ हो चुका है कि 2027 में देश की आधी आबादी सत्ता परिवर्तन करके रहेगी वही हमारी माताएं बहने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में आस्था जताते हुए पंडित समरजीत के नेतृत्व में समाजवादी झंडा पड़कर सत्ता परिवर्तन का शंखनाद कर दिया है।इस मौके पर राजकला देवी, माधुरी निषाद, कैलाश, सुनीता, मीना देवी, उषा निषाद, रीता, पूजा, पूजा, अर्चना, रेखा, संगीता, संगीता, आशा, साधना, साधना, शकुंतला, रूपा।

सावन के पहले दिन शिव मंदिरों में उमड़ी आस्था, हर-हर महादेव से गूंजे परिसर

गोरखपुर, (संवाददाता)। सावन का महीना बृहस्पतिवार से शुरू हो गया। सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं की ओर से शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में पूजन–अर्चन का दौर सुबह से ही जारी है । हर–हर महादेव व बम–बम भोले के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। शहर के कुनराघाट स्थित महादेव झारखंडी मंदिर, राजघाट स्थित बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर और अंधियारी बाग स्थित मानसरोवर मंदिर के साथ–साथ शहर के बेतियहाता हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, गोरखनाथ मंदिर के शिव मंदिर सहित शहर के विभिन्न मोहल्ले में स्थापित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बृहस्पतिवार सुबह से ही श्रद्धालुओं के जलाभिषेक कर रहे हैं। कुनराघाट स्थित महादेव झारखंडी मंदिर में श्रद्धालु सुबह पांच बजे से ही दर्शन–पूजन कर जलाभिषेक कर रहे हैं। इसके साथ ही राजघाट स्थित बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था देखने को मिल रही है। बारी–बारी से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। वहीं मानसरोवर मंदिर और गोरखनाथ मंदिर में भी श्रद्धालु अपनी आस्था निवेदित कर रहे हैं।

जमीनी विवाद को लेकर 120 फीट टावर पर चढ़ा युवक

प्रयागराज, (संवाददाता)। सोरांव थाना क्षेत्र स्थित लहटी चौराहा पर एक युवक अचानक पास में लगे 120 फीट मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया। पिछले 8 घंटे से वह चढ़ा है अभी तक नहीं उतरा है उतारने का प्रयास जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोरांव थाना क्षेत्र स्थित लहटी निवासी लवकुश के अपने साथ जमीन से संबंधित दस्तावेज और शिकायत पत्र लेकर टावर पर चढ़ा गया। युवक का आरोप है कि जमीन विवाद के मामले में उसे लंबे समय से न्याय नहीं मिल रहा है और उसकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी से नाराज होकर उसने विरोध जताने के लिए यह कदम उठाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अधिकारियों ने युवक को समझाने का काफी प्रयास किया। इसी दौरान तहसीलदार सोरांव ने उससे कहा कि सिर्फ मजे लेने के लिए टावर पर चढ़े हो? इस पर युवक ने नाराजगी जताते हुए जवाब दिया कि खूब काजू–बादाम खाए हो, हमें न्याय नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद उसने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जब तक उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, वह नीचे नहीं उतरेगा।

जिला अस्पताल से बच्ची को अगवा कर सिपाही ने की हत्या, हिरासत में

भदोही, (संवाददाता)। डायल–100 में तैनात सिपाही अभिषेक यादव ने जिला अस्पताल से 10 वर्षीय बच्ची को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मूल रूप से गाजीपुर निवासी अभिषेक को हिरासत में ले लिया है और उसे लेकर देर रात तक शव की तलाश में जुटी रही। पुलिस के अनुसार, आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले बच्ची के पिता पिछले चार वर्षों से गोरखपुर में परिवार के साथ रहकर ई–रिक्शा चलाते हैं। 27 जुलाई को उनकी बड़ी बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे 10 वर्षीय बच्ची अपनी बड़ी बहन के लिए खाना लेकर जिला अस्पताल पहुंची थी। बहन को खाना खिलाने के बाद रात करीब नौ बजे वह घर के लिए निकली लेकिन वापस नहीं पहुंची। काफी देर तक इंतजार के बाद परिजन ने अस्पताल परिसर और आसपास उसकी तलाश की। रिश्तेदारों और परिचितों से जानकारी लेने के बाद भी जब बच्ची का पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। अस्पताल में भर्ती 13 वर्षीय बड़ी बहन ने पुलिस को बताया कि दोनों बहनें अस्पताल परिसर में बैठकर खाना खा रही थीं। इसी दौरान पुलिस की वर्दी पहने एक युवक वहां आया और उनसे पता पूछने लगा। आरोप है कि युवक ने दोनों बच्चियों से कहा कि वह बाइक से घर छोड़ देगा। बड़ी बहन के मना करने के बाद भी आरोपी छोटी बहन को साथ चलने के लिए दबाव बनाता रहा। इसके बाद वह काफी देर तक बच्ची के आसपास घूमता रहा। बच्ची के अस्पताल से निकलने के बाद आरोपी उसके पीछे चला गया।

नाली के बिना विकास का दावा, बाजारों में तैरती हकीकत

भदोही, (संवाददाता)। जिले के ग्रामीण बाजारों में पानी निकासी का इंतजाम न होने से बारिश के बाद चार से पांच दिनों तक जलभराव बना रहता है। बाजारों में व्यापारियों की दुकानों के सामने हफ्तों तक जमा पानी एक ओर बीमारियों को न्योता दे रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों के कारोबार को भी प्रभावित कर रहा है। जिले के प्रमुख बाजारों में औसतन छह से आठ हजार लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। जिम्मेदारों की उदासीनता से ग्रामीण बाजारों की तस्वीर लगातार खराब हो रही है। जिले में कुल 546 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें सात निकायों के अलावा बाबूसराय, महाराजगंज, देवनाथपुर, सर्राई, चौरी, मोढ़, महजूदा, पाली, नागमलपुर, कोईरौना और सीतामढ़ी जैसे अनेक ग्रामीण बाजार हैं। इन बाजारों पर आसपास के गांवों की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। मुख्य बाजारों से दूर बसे इन बाजारों में हर दिन औसतन आठ से 10 हजार लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में व्यापारियों के साथ ग्राहकों को भी परेशानी होती है। बारिश के दिनों में इन बाजारों की स्थिति और खराब हो जाती है। मुख्य सड़कों के किनारे बसे इन बाजारों में नालियों का निर्माण न होने के कारण हल्की बारिश में ही सड़क के दोनों ओर पानी भर जाता है। यह पानी हफ्ते भर से अधिक समय तक जमा रहता है, जिससे व्यापार प्रभावित होता है। जिले की मुख्य सड़कों के किनारे बसे इन बाजारों में सड़क निर्माण के दौरान नाली का प्रस्ताव भी शामिल होता है, लेकिन नाली का निर्माण नहीं हो पाता। कुछ दिन पहले ज्ञानपुर–भदोही मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव आया। चौड़ीकरण में देवनाथपुर और ज्ञानपुर के पटेल नगर में नाली निर्माण का भी प्रस्ताव है, लेकिन अब तक नाली नहीं बन सकी है। इसी तरह सुरियावां–पाली मार्ग स्थित महजूदा बाजार में पटरी का निर्माण नहीं किया गया, जिससे बारिश होते ही चारों ओर पानी भर गया। भदोही–ज्ञानपुर मार्ग स्थित देवनाथपुर बाजार में बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही पानी भर जाता है। नाली न होने से सड़क के दोनों ओर और बीच सड़क तक पानी भरता है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।